

प्रक.

श्री एनसीओ जाशी,
 अवर सचिव,
 उत्तरांचल शासन।

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
 उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
 देहरादून।

कक्षा विभाग

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2006-07 में निजी नलकूपों/पम्पसेटों के कर्जीकरण/विद्युत संयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

सम्बन्धित विषयक वित्त अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या 908/XXVIII/1/2006, दिनांक 24.04.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी नलकूपों/पम्पसेटों के कर्जीकरण/विद्युत संयोजन हेतु रू० 4950 हजार (रू० चत्वारस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में वित्त शासि के अधीन व्यव करने हेतु आपके निर्देशन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सार्व स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून से प्रविष्टाधिकारित वित्त कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कर गी०एल०एल में रखी जायेगी जिसका आहरण अमात्रावकाश एवं कर्म की प्रगति के आधार पर तीन किस्तों में किया जाएगा। प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ही दूसरी किस्त का आहरण किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरी किस्त का आहरण भी द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर किया जायेगा। मासिक रूप से योजना की वित्तीय/वैयक्तिक प्रगति का निवेदन एवं कर्जीकृत नलकूपों/पम्पसेटों की सूची जनपदवार/विभागाध्यक्षवार लगानी सूची व उसका सापेक्ष नाम धनराशि का उल्लेख करते हुए शासन को प्रस्तुत की जायेगी।
- 3- विभागाध्यक्ष/जनपदवार लगानियों की सूची व उनके सापेक्ष व्यव धनराशि का निवेदन दिनांक 31.03.2007 तक शासन को पुरितकाल के रूप में भी उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि गैर वकीले को उसका निवेदन भी कारण सहित शासन को तत्त स्थिति तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- 4- आवश्यक सामग्री का मुगत्तन सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जांच के उपरान्त ही किया जायेगा तथा सामग्री का गुणवत्ता के लिये राज्य अधीनकारी को अभिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाय।
- 5- शासनादेश सं० 181/वी-3-अ/2003, दिनांक 30.01.2003 में दिये गये सामान्य निर्देशों के अनुरूप कार्यावाही की जायेगी एवं उसके संलग्न प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इस हेतु सर्वप्रथम संलग्न प्रार्थना पत्रों का निरतारण प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- 6- व्यव करने से पूर्व जिन मामलों/योजनाओं पर बजट हेतुमूल, फाईनेंसियल हेल्ड बुक, स्टॉर फॉर्म एवं अन्य सार्वजनिक नियमों तथा अन्य सहाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य प्राधिकारी की प्राथमिक स्वीकृति आवश्यक है, इसमें गृह प्राप्त करने के ही कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।
- 7- यदि तत्त कर्मों में निर्माण कार्य करने जाते हैं तो इनके आगमन बजाकर उस पर सक्षम स्तर की तकनीकी परीक्षा के उपरान्त सक्षम तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जाय।

C

8- नलकूप लगाने जाने से पूर्व लगानेवालों से इस बात की लिखित जानकारी ले ली जायेगी कि क्या उचित नलकूपों के अनुस्थापन का पूर्ण दायित्व उन्हें का होना और इसके मासु रखने के लिये विभाग द्वारा शेफार्ड भी अपनाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही निजी नलकूप संयोजन इस प्रतिवन्द के साथ निर्गत किया जाय कि उत्तरांचल गानर कन्सोलिडेशन लिमिटेड, सिंचाई विभाग अथवा नू जल सर्वेक्षण विभाग, जैसी भी स्थिति हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि भूमिगत पानी के परिसंचरण में नलकूप निर्माण हेतु कोई तकनीकी बाधता/रोक नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत एक बार उचित नलकूप का पुनः उन्नी योजना के अन्तर्गत उन्नीकरण नहीं किया जायेगा।

9- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित दायित्वों में उन्नी संज्ञान/निर्गत सुरक्षा के पूर्ण समाय मिले जायेगे तथा संयोजन इलेक्ट्रॉनिक मीटर मुक्त होगा।

10- व्यव उन्नी मदों में किया जायेगा जिनके लिये स्वीकृत किया जा रहा है।

11- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु यूनिटीएल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

12- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण समाय के उपरान्त अब एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि से उन्नीकृत समस्त गणों की लगानेवाले वितरण सहित (लागत व व्यव सुचना सहित) सूचना साशन के उपलब्ध करायी जायेगी। यह सूची सामान्य व एक्सीसीपी/टीएसपी/पी वार अलग-अलग दी जायेगी।

13- सामान्य एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ इस योजना में धनराशि पृथक से निर्गत की जा रही है।

14- इस धनराशि से सर्वप्रथम मत चार में 60 प्रतिशत किए गये कार्यों को पूर्ण किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यव मासु वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ आय-व्यय के अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत लेखाधीन 2801-मिजली-00-मागीण वित्तीयकरण आयोजनागत-000-अन्य व्यव-04-निजी नलकूप/पम्पसेट में निरुत संयोजन योजना-00-20-सामान्य अनुदान/अनुदान/राज सहमता के नामे आला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अक्षराधीन संख्या 173/XXVI(2)/2006, दिनांक 08 जून, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डॉ० एन०पी० जोशी)

अपर सचिव

संख्या 727/1/2006-6(1)/31/2006, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महोदय/आचार, उत्तरांचल।
- 2- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 3- कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 5- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग/एन०आई०सी०, उत्तरांचल शासन।
- 6- श्री एन०एच० भं, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के मा० मंत्रालय की जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 8- फाईल में रखा।

आज्ञा से,

22/6

(एन०एच० रोगवाल)

अनु सचिव